गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 164
दि. 13.10.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दुर्गापुर गैंगरेप कांड से ममता सरकार पर घिरा बंगाल: विपक्ष का हमला, उठे सवाल — क्या सुरक्षित हैं राज्य की महिलाएं?

(जीएनएस)। बर्धमान। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप की घटना ने राज्य की राजनीति, प्रशासन और समाज को झकझोर दिया है। यह घटना एक निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के पास शुक्रवार रात हुई, जब ओडिशा की रहने वाली छात्रा अपनी सहेली के साथ भोजन करने बाहर गई थी। लौटते वक्त तीन अज्ञात युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया, उसे पास के जंगल की ओर घसीट लिया और बारी-बारी से बलात्कार किया। वारदात के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शनिवार सुबह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना

ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान — “लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए” — राज्य की सियासत में बवंडर बन गया। विपक्षी दलों ने इसे संवेदनहीन, अमानवीय और “महिलाओं का अपमान” करार देते हुए तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि बंगाल में कानून का शासन खत्म हो चुका है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा, “ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। जब एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित हैं, तो यह राज्य के लिए कलंक है।”

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ा है क्योंकि सख्त सजा नहीं दी जाती। “किसी को फांसी पर लटकते नहीं देखा गया है, इसलिए अपराधी बेखौफ हैं,” उन्होंने कहा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने इस कांड की कड़ी निंदा की और पीड़िता को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “ममता बनर्जी न केवल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गृह मंत्री भी हैं। उनका यह बयान महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाता है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए।”

यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल ऐसी घटनाओं से सुर्खियों में आया हो। 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप और हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया था। डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। इससे पहले कसबा लॉ कॉलेज, डायमंड हार्बर, संदेशखाली, हंसखाली और कामदुनी जैसे मामलों ने भी राज्य की छवि को गहरी चोट दी थी।

कामदुनी केस (2013) में कॉलेज छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी — यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2022 में हंसखाली में 14 वर्षीय लड़की की रेप के बाद हत्या ने फिर आक्रोश भड़काया। 2023 के डायमंड हार्बर और 2020 के संदेशखाली कांड में भी विरोध प्रदर्शन हुए।

इन घटनाओं की श्रृंखला और ममता सरकार की प्रतिक्रियाओं ने यह सवाल और गहरा कर दिया है कि क्या “सोने का बंगाल” अब महिलाओं के लिए सुरक्षित है? राज्य की जनता, प्रशासन और न्याय व्यवस्था के सामने यह प्रश्न अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौती बन गया है — कि आखिर कब तक महिलाओं की अस्मिता राजनीति की बहसों में दबकर रह जाएगी?

आईपीएस वाई पूरन कुमार की रहस्यमय मौत पर बवाल, महापंचायत ने डीजीपी को हटाने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वाल्मीकि समाज में उबाल

(जीएनएस)। चंडीगढ़ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को वाल्मीकि समाज की विशाल महापंचायत ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। महापंचायत ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो चंडीगढ़ और हरियाणा के सभी सफाई कर्मचारी काम छोड़ देंगे। इसके साथ ही समाज के प्रतिनिधियों ने फैसला किया कि राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। 7 अक्टूबर को 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन उनके घर से मिले सुसाइड नोट ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। इस खुलासे के बाद न सिर्फ पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई, बल्कि वाल्मीकि समाज में भी गहरा आक्रोश फैल गया। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अमनीत कुमार, जो उस समय विदेश में थीं, घटना की जानकारी मिलते ही भारत लौट आईं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि एफआईआर में जानबूझकर कई नामों को शामिल नहीं किया गया और जांच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। परिवार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वाल्मीकि समाज ने रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई, जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि अगर डीजीपी को नहीं हटाया गया तो अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेशभर के करीब 5,000 सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

BJP और JDU को बराबर सीटें, NDA ने बिहार चुनाव 2025 के लिए फॉर्मूला तय किया

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम रूप दे दिया है। इस तय फॉर्मूले के अनुसार जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ही 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को छह-छह सीटें दी गई हैं। इस समझौते के बाद गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई “बड़ा भाई” नहीं है और दोनों प्रमुख दल बराबर के साझेदार हैं। सीट बंटवारे में सबसे बड़ा लाभ चिराग पासवान को मिला। भाजपा शुरू में उन्हें केवल 22 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी मांग पर कायम रहते हुए 29 सीटें

हासिल कीं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी पसंद की तीन प्रमुख सीटें — हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर — भी अपने खाते में रख ली हैं। हालांकि, पिछली बार 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद लोजपा (रामविलास) केवल एक सीट जीत पाई थी, इसलिए इस बार चिराग के सामने अपनी “स्ट्राइक रेट” साबित करने की चुनौती होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को छह-छह सीटें देकर भाजपा-जदयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन में कोई दल उपेक्षित नहीं रहेगा। सूत्रों के अनुसार, उपेंद्र कुशवाहा को उजियारपुर, महुआ, दिनारा, सासाराम, बाजपट्टी और मधुबनी जैसी सीटें मिल सकती हैं। मांझी शुरू में असंतोष में थे और उन्होंने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद वे सहमत हो गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, “हम आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ हैं।” इस बार जदयू और भाजपा दोनों ने सीटों में कटौती की है — जदयू 115 से घटकर 101 और भाजपा 110 से घटकर 101 पर आ गई है। यह कदम गठबंधन में शक्ति संतुलन बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन राजद-कांग्रेस ने अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, NDA का यह फॉर्मूला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, जो बिहार में सत्ता बनाए रखने और चुनावी बढ़त हासिल करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप का मध्य पूर्व शांति अभियान: मिस्र में 20 देशों के साथ युद्धविराम की ऐतिहासिक कोशिश

(जीएनएस)। वाशिंगटन से रविवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐतिहासिक और जोखिमपूर्ण मिशन पर रवाना हुए हैं। उनका यह दौरा इजराइल और मिस्र को केंद्र में रखकर मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की एक बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ट्रंप का उद्देश्य गाजा में जारी इजराइल-हमास युद्ध को रोकने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप देना है। अगर यह मिशन सफल होता है, तो यह न केवल क्षेत्र में बल्कि विश्व राजनीति में भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप सबसे पहले इजराइल पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे कनेसेट—इजराइल की संसद—में

संबोधन देंगे। यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 2008 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को कनेसेट में बोलने का अवसर मिलेगा। उनके इस संबोधन में गाजा संकट, बंधक रिहाई और क्षेत्रीय स्थिरता पर अमेरिकी दृष्टिकोण प्रमुख रहेगा।

दौरे का सबसे महत्वपूर्ण चरण मिस्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शर्म-अल-शेख में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी और ट्रंप इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। इस बैठक में गाजा पट्टी में तत्काल युद्धविराम, मानवीय सहायता वितरण, और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर विस्तृत चर्चा होगी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में हमास 48 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की पुष्टि हुई है। इसके बदले इजराइल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और गाजा के कुछ हिस्सों से अपनी सेनाएं आंशिक रूप से हटा लेगा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियां खाद्य सामग्री, दवाइयां और पानी जैसी मूलभूत वस्तुएं गाजा में पहुंचाएंगी। यह चरण 72 घंटों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि बंधकों की पहली खेप की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है। उन्होंने अपने प्रस्थान से पहले कहा, “अगर यह समझौता काम करता है, तो यह न केवल युद्ध रोकने का बल्कि भरोसा बहाल करने का भी पहला कदम होगा।” हालांकि, इस शांति प्रक्रिया के रास्ते में कई पेचीदगियां हैं। सबसे कठिन सवाल यह है कि युद्ध के बाद गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा। इजराइल यह नहीं चाहता कि हमास फिर से शासन में लौटे, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) को लेकर भी राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका और मिस्र चाहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र के तहत गाजा का पुनर्निर्माण हो, लेकिन इस पर सभी पक्षों की सहमति अभी नहीं बन पाई है। इजराइल ने दोहराया है कि अगर उसकी सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो वह सैन्य अभियान दोबारा शुरू कर सकता है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा की मानवीय स्थिति “अकल्पनीय रूप से गंभीर” हो चुकी है — अस्पतालों में दवाएं खत्म हैं, बिजली बंद है, और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं।

ट्रंप प्रशासन ने इस मिशन के तहत इजराइल में एक अमेरिकी सहायता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र गाजा में राहत सामग्री, सुरक्षा समन्वय और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। इसके संचालन के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैनिक भेजे जाएंगे। ट्रंप इसे “अब्राहम समझौतों” की अगली कड़ी बताते हैं — जिनके तहत 2020 में कई अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य किए थे। ट्रंप की योजना है कि इस नई शांति प्रक्रिया में सऊदी अरब और इंडोनेशिया को भी शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित की जा सके। हालांकि, सऊदी अरब ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का स्थायी समाधान नहीं होता, वह इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देगा।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात देकर रचा इतिहास: महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन-चेज

(जीएनएस)। विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का रोमांचक मुकाबला इतिहास में दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 331 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को महज 49 ओवरों में चेज कर लिया, जिससे पूरा स्टेडियम और क्रिकेट जगत स्तब्ध रह गया।

भारतीय टीम ने शुरुआत में दमदार प्रदर्शन दिखाया। स्मृति मंधाना ने शानदार 87 रनों की पारी खेली, जबकि युवा खिलाड़ी प्रतीका सिंह ने अपने वर्ल्ड कप करियर की पहली फिफ्टी लगाई। हरमनप्रीत कौर और

ऋचा घोष ने अंत में तेज़ रन जोड़कर टीम का स्कोर 331 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह लक्ष्य असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों ने अपनी संयमित और आक्रामक रणनीति से इसे संभव कर दिखाया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एलीसा हीली ने बेहतरीन नेतृत्व दिखाते हुए 96 रनों की कप्तानी पारी खेली। उनकी साथी बेथ मूनी ने 78 रन बनाए और दोनों ने मिलकर भारत की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ताहलिया मैक्ग्रा और एश्ले गार्डनर ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जीत को अपनी झोली में डाल लिया। भारत की ओर से पूनम यादव और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट झटके, लेकिन बाकी गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे।

भारत ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था — श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर उसने टूर्नामेंट की शुरुआत विजयी ढंग से की थी। मगर साउथ अफ्रीका से हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से मिली यह शिकस्त टीम इंडिया के लिए झटका साबित हुई है। इस हार के बावजूद भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन आने वाले मुकाबले अब करो या मरो की स्थिति जैसे होंगे।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत फिर से साबित कर दी है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराने के बाद अब भारत जैसी मज़बूत टीम को मात देना यह दर्शाता है कि कंगारू टीम की तैयारी बेहद मजबूत है। श्रीलंका के खिलाफ उसका मैच बारिश से धुल गया था, मगर इस ऐतिहासिक जीत ने उसे अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा — “हमने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी में लय खो दी। हमें डेथ ओवर्स में और अनुशासन की ज़रूरत है। हम अगले मैच में और मजबूती से लौटेंगे।”

क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह मैच महिला क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर बन गया है, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने का साहस और सफलता अब तक किसी भी टीम ने नहीं दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उसे “वर्ल्ड चैम्पियन” कहा जाता है — और भारत के लिए यह हार चेतावनी है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर विभाग में परिपूर्णता जरूरी है।

बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से अफरातफरी, 12 यात्री घायल, जांच के आदेश जारी

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक यात्रियों की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। यह हादसा शाम करीब साढ़े छह बजे हुआ, जब एक साथ तीन ट्रेनें अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आ गईं और हजारों यात्री प्लेटफॉर्म छोड़कर फुटओवर ब्रिज की ओर भागने लगे। संकरी सीढ़ियों पर अचानक दबाव बढ़ने से लोग एक-दूसरे से टकराने लगे, और कुछ यात्री फिसलकर गिर पड़े। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी में 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना का कारण स्टेशन पर अचानक बढ़ी भीड़ और रेलवे प्रशासन की लापरवाही रही। यात्रियों का कहना था कि प्लेटफॉर्म पर कोई नियंत्रण नहीं था, और जैसे ही तीन ट्रेनें एक साथ आईं, लोग जल्दी-जल्दी सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। “सीढ़ियों पर इतनी भीड़ थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था,” एक यात्री ने बताया। “कई लोग गिर पड़े और उनके ऊपर लोग चढ़ गए।” घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। राहत कार्य शुरू किया गया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। प्लेटफॉर्मों पर मौजूद यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत जांच के आदेश दिए गए।

पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर ट्रेनें लगभग एक ही समय पर लगने के कारण भीड़ अचानक बढ़ गई थी। स्टेशन पर पहले से ही त्योहारी सीजन के चलते यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक थी। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भीड़ नियंत्रण के नए उपाय लागू किए जाएंगे और फुटओवर ब्रिज पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी।

इस हादसे के बाद यात्रियों में गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। “त्योहारी सीजन में हर साल भीड़ बढ़ती है, लेकिन रेलवे हर बार गलती दोहराता है,” एक स्थानीय व्यापारी ने कहा। लोगों ने यह भी मांग की कि स्टेशन के फुटओवर ब्रिज को चौड़ा किया जाए और प्लेटफॉर्म पर डिजिटल भीड़ अलर्ट सिस्टम लगाया जाए।

संपादकीय

मोदी-ट्रंप ने की ट्रेड डील पर चर्चा

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है, लेकिन बातचीत का जारी रहना सकारात्मक संकेत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच वार्ता में ट्रेड का जिक्र आना बताता है कि मतभेद कम हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप के रवैये को देखते हुए इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सही दिशा में प्रगति- दोनों नेताओं के बीच गाजा शांति समझौते पर बात होनी थी, पर ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। दोनों तरफ का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल लंबे समय से डील पर बात कर रहा है। रंप ने इस मुद्दे पर भले कई बयान दिए हों, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से डील पर कभी कुछ नहीं कहा गया। अब उनकी तरफ से जिक्र होने का यही मतलब निकलता है कि बात सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

जल्दबाजी नहीं- भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तीन साल से बातचीत चल रही थी। तब जाकर इस जुलाई में पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हो सके और अब भी इसे लागू करने में यह पूरा साल गुजर जाएगा। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौते के तुरंत फाइनल हो जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और वह भी तब, जब कुछ मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है।

बीच का रास्ता- अमेरिकी शिकायत भारत से होने वाले व्यापार घाटे, कृषि व डेयरी उत्पाद और रूसी तेल को लेकर है। अब ऐसा लग रहा है कि बीच का रास्ता निकलने लगा है। भारत ने अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल, गैस और एथेनॉल खरीदने का प्रस्ताव दिया है।

लचीलापन चाहिए- हालांकि, समझौता तभी फाइनल हो सकता है और तभी उस पर सफलतापूर्वक अमल किया जा सकता है, जब दोनों पक्ष लचीला रुख अपनाएं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जरूरतों को समझना होगा। अमेरिका के साथ डील का मतलब यह नहीं हो सकता कि भारत अपने दूसरे व्यापारिक सहयोगियों को किनारे कर दे।

दोनों की जरूरत- ट्रंप के दौर में अमेरिकी पॉलिसी अनिश्चित रही है, तो बातचीत की मेज पर भारतीय वार्ताकार अब भी रिलैक्स नहीं हो सकते। उन्हें मजबूती से पक्ष रखना होगा और US को समझाना होगा कि यह डील दोनों ही देशों के लिए जरूरी है। यह तभी हो सकती है जब संवाद, सहयोग, एक-दूसरे की चिंताओं की समझ और आपसी सम्मान हो।

बसपा ने फिर दिखाई ताकत, मायावती के सियासी दांव से सपा को 'तनाव'

> बसपा रैली में बहिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ-साथ मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता सतीशचंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की भी लॉन्चिंग हो गई है। मायावती ने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की।

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक की चहल-पहल दिखने लगी है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती ने मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई राजनैतिक संदेश दिए। बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। बहिन मायावती ने न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की अपितु यह भी कहा कि यदि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जुमला न साबित हुआ तो वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी। बहिन मायावती अपनी 2007 की रणनीति को अपनाते हुए पुनः सामाजिक न्याय को आधार बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ऐसा संकेत उनकी रैली से मिलता है। उन्होंने अपनी रैली मे भीड़ जुटा कर यह संदेश दे दिया है कि उनका कोर वोटबैंक जाटव व दलित अभी भी उनके साथ है, भले ही इस समय उनके पास विधानसभा में केवल एक विधायक और मात्र 9 प्रतिशत वोट है। बहिन मायावती अपनी रैली में भाजपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान पर नाटकबाजी कर रही है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल लगाकर बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया।उन्होंने केंद्र सरकार में रहने पर उन्हें आयकर और सीबीआई की जांच में फंसाने की कोशिश की ताकि डा. आंबेडकर और कांशीराम के कारवां को रोका जा सके। अब उसी कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा पर तीखा हमला बोलते हुए बहिन मायावती ने कहा कि सपा की सराकर में दलितों व पिछड़ों का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ। उन्होंने सपा सरकार की अराजकता पर हमला किया।

बसपा रैली में बहिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ-साथ मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता सतीशचंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की भी लॉन्चिंग हो गई है। मायावती ने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की। जातीय समीकरण साधने के लिए सतीशचंद्र मिश्र के अलावा उमाशंकर सिंह को भी मंच पर जगह दी गई। प्रशंसनीय बात है कि इस रैली की तैयारी बहिन मायावती और उनके कार्यकर्ता बहुत ही शांत व अनुशासित तरीके से कर रहे थे। बसपा व बहिन मायावती अपने वोटर्स के मध्य बहुत समझदारी के साथ संपर्क बनाती हैं और यही कारण है कि उनका वोटबैंक काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है; यद्यपि 2017 के बाद जाटव मतदाता में सेंध लग चुकी है जिसे फिर से भरोसा दिलाकर वापस लाना बहिन जी के लिए एक कठिन चुनौती है। लंबे समय से बहिन जी का नाम तथा आवाज़ केंद्रीय राजनीति से दूर रहने के कारण दलित राजनीति में चंद्रशेखर "रावण" जैसे लोगों का उभार हुआ है जो बसपा के परम्परागत वोटबैंक पर दावा ठोंक रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने भले ही जोर देकर कहा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी किंतु यह फिलहाल संभव नहीं प्रतीत हो रहा हें क्योंकि बसपा का जो राजनैतिक समीकरण हे उस आधार पर उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए कम कम के कम 30 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी और वह अभी मात्र 9 प्रतिशत ही है। प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों में बसपा कार्यकर्ताओं की धरातल पर कड़ी मेहनत के बाद यह मत प्रतिशत 15-20 पहुँच सकता है। बहिन जी ने खुले मंच से जिस प्रकार से योगी जी की प्रशंसा की वह बसपा के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि संभव है इससे प्रदेश का मुस्लिम मतदाता सपा गठबंधन के साथ जाना पसंद करे।

भले ही बसपा नेत्री मायावती का 2027 में अपने बलबूते पर सरकार में आने का दावा अतिशयोक्ति हो किन्तु इससे 2027 में सपा-बसपा गठबंधन की चर्चाओं को विराम लग गया है। साथ ही बहिन जी के दावे से सपा गठबंधन के लिए गहरा तनाव और भाजपा के लिए राहत की सूचना आ गई है।

प्रेरणा

क्रोध से विनाश और धैर्य से उद्धार की कथा

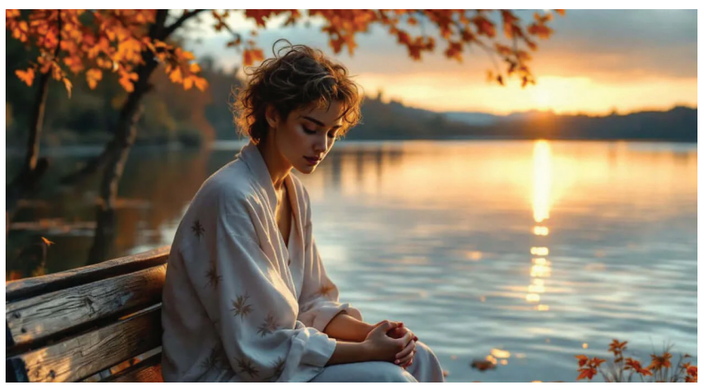

बहुत समय पहले एक महान राज्य था, जहाँ एक राजा अपने पराक्रम, नीति और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उससे प्रेम करती थी, क्योंकि वह हर निर्णय बड़े विवेक और करुणा से लेता था। परंतु इस राजा की एक ही कमजोरी थी—उसका क्रोध। जब भी कोई उसके आदेश की अवहेलना करता या कोई कार्य उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो उसका चेहरा अंगारों-सा लाल हो जाता और उसकी आवाज़ सिंह की गर्जना की तरह गूँज उठती। उस समय वह क्या कहता, क्या करता, उसे खुद भी नहीं पता होता।

एक दिन दरबार में एक मामूली बात पर उसने एक निर्दोष मंत्री को कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। सभी दरबारी मौन हो गए। कोई साहस नहीं कर सका कि राजा को रोके, क्योंकि सब जानते थे कि क्रोध की स्थिति में राजा किसी की नहीं सुनता। मंत्री ने folded hands से कहा, "राजन, मैं अपराधी नहीं हूँ, परंतु यदि मेरे दंड से आपका मन शांत होता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ।" इतना कहते ही उसने सिर झुका लिया।

राजा का हृदय जैसे आग बन गया था, और उसी क्षण उसने दंड का आदेश लागू कर दिया। मंत्री को कारावास में डाल दिया गया। पर जैसे ही रात ढली, राजा की अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। भीतर से आवाज़ आई — "तुमने क्या किया, राजन? क्रोध के आवेग में तुमने न्याय का गला घोंट दिया।" वह बेचैन हो उठा। नींद आँखों से दूर थी। अगले दिन उसने आदेश रद्द कर मंत्री को मुक्त किया और क्षमा माँगी। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा — "महाराज, क्षमा तो उन्हें चाहिए जो गलती को पहचानने से इंकार करें। आपने तो अपनी भूल स्वीकार की है। ईश्वर आपको बुद्धि और धैर्य प्रदान करें।"

इस घटना के बाद राजा ने प्रण लिया कि वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करेगा। उसने दरबार में एक नियम बनाया — "जब भी मुझे क्रोध आए, मैं पहले एक पात्र में पानी भरकर उसमें अपना चेहरा देखूँगा।" जब अगली बार किसी ने उसे क्रोधित किया, उसने वही किया। उसने देखा कि उसके चेहरे पर जो अग्नि और विकृति थी, वह भयावह थी। उसे लगा मानो वह खुद कोई दानव बन गया हो। उसी क्षण उसे महात्माओं की बातें याद आईं — "क्रोध में मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता।" वह सोचने लगा — "क्रोध क्षणिक पागलपन है। यह बुद्धि को अंधा कर देता है। जिस क्षण क्रोध हावी होता है, उसी क्षण विवेक नष्ट हो जाता है। वही क्षण विनाश की ओर ले जाता है।" उस दिन से उसने आत्मसंयम का अभ्यास शुरू किया। जब भी क्रोध आता, वह मौन हो जाता, गहरी श्वास लेकर मन को शांत करता। धीरे-धीरे उसका स्वभाव बदल गया।

राजा ने अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दी — "बेटा, क्रोध की अग्नि में सबसे पहले स्वयं जलता है। किसी पर गिरने से पहले उसकी ज्वाला अपने धारक को ही भस्म कर देती है। जिस मन में क्रोध है, वहाँ बुद्धि ठहर नहीं सकती। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है — 'क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति के भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट हुई तो विनाश निश्चित है।'"

राजकुमार ने पूछा — "पिताश्री, क्या क्रोध कभी उचित भी हो सकता है?" राजा ने कहा — "हाँ पुत्र, धर्म की रक्षा के लिए जो क्रोध उठता है, वह 'धार्मिक रोष' कहलाता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। परंतु जो क्रोध 'अहम्' से उठता है, वह केवल विनाश का कारण बनता है। उसे तुरंत शांत करना चाहिए।"

कुछ वर्षों बाद वह राजा अपनी संयम और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गया। जो राजा पहले भय से शासन करता था, अब प्रेम और विवेक से राज्य चलाता था। प्रजा उसे "धैर्यधन" कहने लगी।

कथा का सार यही है —

क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले अपने ही घर को जलाती है।

धैर्य, क्षमा और शांति वह जल हैं जो इस अग्नि को बुझाकर जीवन को शीतल बना देते हैं।

जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तव में स्वयं पर शासन करता है, और वही सच्चा राजा कहलाता है।

वातावरण और पर्यावरण: दिखावे से असली जिम्मेदारी तक की कहानी

बारिशें इस बार कुछ अलग रंग में आईं। जैसे ही बादलों ने ज़मीन पर पानी बरसाया, शहरों और गाँवों की सच्चाई सबके सामने आ गई। नालियाँ और नदियाँ अपनी सीमाएँ पार कर गईं, सड़कों पर जलमग्न होते वाहन और घरों में पानी भर गया। कुछ लोगों ने इसे मज़े में लिया और तैराकी का अभ्यास शुरू कर दिया। लेकिन अधिकांश नागरिक परेशान और मजबूर हो गए। प्रशासन पुराने ढर्रे में उलझा रहा, ड्रेनेज सिस्टम अस्त-व्यस्त था और लोग अपने घरों में फँसे हुए, आपदा की भयावहता का सामना कर रहे थे।

इस आपदा के दौरान "अवसर की तलाश" करने वालों की परम्परा भी जीवित रही। कुछ लोग राहत कार्यों के नाम पर दिखावा कर रहे थे, कुछ लोग फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। शासन और प्रशासन बार-बार अपील करते रहे, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में चेतावनी दी गई, लेकिन लोग वातावरण और पर्यावरण के प्रति अपनी लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं थे।

हमारी सांस्कृतिक परम्परा यही सिखाती है कि जंगल बचाकर, पानी सुरक्षित करके और पौधों की रक्षा कर हम वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। भाषण देने वाले बड़े आत्मविश्वास के साथ समाज को सभ्य मानते हुए यही कहते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। लोग अब पहले जैसे सभ्य नहीं रहे। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कर्म करना कठिन लगने लगा है। अब लोग रैलियों और बैनर मार्च में शामिल होने को ही पर्यावरण सुरक्षा मान लेते हैं।

हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना करने वाले परिषद के अध्यक्ष इसे प्रतीकात्मक महत्व देते हैं। रैली में शामिल लोग नारे लगाने से पहले बोतल में पानी, खाना, सेब और केले जैसे मौसमी फलों का भोग लगाते हैं। टी-शर्ट्स और उन पर छपे संदेशों, दस्तानों और हरी टोपी पर भारी खर्च किया जाता है। रैली में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद रहते हैं, जिन्होंने अपने मकानों का पुनर्निर्माण या अवैध कालोनी का निर्माण कर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया हो। ऐसे शानदार और दिखावटी आयोजनों में पर्यावरण केवल प्रतीक बनकर रह जाता है, उसका वास्तविक संरक्षण कहीं खो जाता है।

हमारे समाज के अधिकांश लोग जानते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। फिर भी यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला है कि लोग वातावरण और पर्यावरण में अंतर नहीं समझते। दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन स्वयं जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं। आसान उपाय करना भी कठिन लगता है।

महिलाएं इस क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा सकती हैं। घर में प्लास्टिक कम करना, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना और पौधों को मिट्टी के गमलों में लगाना जैसे कदम प्रभावशाली हो सकते हैं। प्लास्टिक के फूल छोड़कर इनडोर पौधे रखना, कपड़ों के थैले का इस्तेमाल करना और पैक्ड सामान सीधे थैले में डाल लेना आसान और प्रभावशाली उपाय हैं।

'रियूज़, रिड्यूस, रिपेयर, रिसाइकिल और रिकवर' — इन पांच नुस्खों को अपनाकर हम जीवन के पांच तत्वों — आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी — को अपने हिस्से का फायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन यह आसान काम भी आसान नहीं लगता। अक्सर लोग पर्यावरण को केवल वातावरण समझकर भूल जाते हैं, जबकि असली जिम्मेदारी उनके रोज़मर्रा के कार्यों में छिपी है।

बारिश के पानी में डूबे शहर और गाँव हमें यही संदेश देते हैं कि केवल दिखावा करने या प्रतीकात्मक कार्य करने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता। वास्तविक संरक्षण छोटे-छोटे कर्मों और नियमित आदतों में छिपा है। अगर हम यह समझ लें कि हर पौधा, हर गमला, हर थैली और हर बूँद पानी महत्वपूर्ण है, तो हम दिखावे से हटकर वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि पर्यावरण की रक्षा केवल भाषणों, रैलियों और फोटो ऑप्स तक सीमित नहीं रह सकती। इसे अपने घर, अपने समुदाय और अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। असली चुनौती यही है कि हम अपने छोटे-छोटे कदमों से बड़ा बदलाव ला सकें। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, पर्यावरण केवल एक सपना बनेगा, और मौसम की आपदाएँ हमारे लिए रोज़मर्रा का संकट।

वास्तविक कहानी यही है कि वातावरण और पर्यावरण केवल दिखावे में नहीं, कर्मों में बचते हैं। छोटे-छोटे बदलाव, नियमित आदतें और जिम्मेदार व्यवहार ही इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और जब यह समझ लोग अपनाएँगे, तभी बारिश, बाढ़ और प्रदूषण जैसी आपदाएँ भी हमें कमजोर नहीं कर पाएँगी।

अभियान

सिद्ध महात्मा की चमत्कारी माला से राजा को मदिरापान की लत से मुक्ति मिली

बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी किंतु दुर्भाग्यशाली राजा राज्य करता था। प्रारंभ में वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था, परंतु धीरे-धीरे उसके जीवन में एक ऐसा विष घुल गया, जिसने उसके विवेक और चरित्र दोनों को निगल लिया—वह था मदिरापान का दुर्व्यसन। शुरुआत में उसने केवल उत्सवों और भोजों में आनंद के लिए थोड़ा-बहुत मद्य ग्रहण करना आरंभ किया, लेकिन कालांतर में यह आदत उसके स्वभाव में समा गई। अब वह सुबह से रात तक बिना मदिरा के रह नहीं पाता था।

राजा की इस आदत को देखकर दरबारी और राजकर्मी भी उसका अनुकरण करने लगे। जब भी राजा मदिरा पीता, दरबारियों में प्रतिस्पर्धा होने लगती कि कौन उससे अधिक पिए और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करे। इस प्रकार सारा दरबार एक प्रकार के मद्य-भवन में परिवर्तित हो गया था। राज्य के धर्माचार्य, विद्वान और पुरोहित इस अधःपतन से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने बार-बार राजा को समझाया कि यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा, प्रजा का जीवन दूभर हो जाएगा, और धर्मराज्य की नींव हिल जाएगी, लेकिन राजा पर किसी का प्रभाव न पड़ा। उल्टे, जब उसे अधिक उपदेश सुनने पड़े, तो उसने क्रोध में आकर सबको कारागार में डाल दिया और एक फरमान जारी कर दिया कि जो कोई भी मदिरा की निंदा करेगा, उसे आजीवन कैद दी जाएगी।

यह आदेश पूरे राज्य में भय की तरह फैल गया। लोग अपने घरों में दुखी रहने लगे, राजकाज अस्त-व्यस्त हो गया और प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगी। तभी एक दिन दूर पर्वतों में रहने वाले एक सिद्ध महात्मा को इस राज्य की दुर्दशा का समाचार मिला। वे अद्भुत योगबल वाले संत थे। उन्होंने सोचा कि यदि इस अधर्म का अंत नहीं किया गया, तो न केवल राजा, बल्कि पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ध्यान किया और यह निश्चित किया कि वे स्वयं राजधानी जाकर इस व्यसन का अंत करेंगे।

अगले दिन महात्मा जी राजधानी पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर में उदासी और निराशा फैली हुई है। लोग आपस में धीरे-धीरे बातें करते, पर कोई खुलकर राजा के दोष की चर्चा नहीं करता। महात्मा जी ने नगर के सबसे भीड़भाड़ वाले चौक पर आसन जमाया और ऊँचे स्वर में बोलना आरंभ किया—"मद्यपान के अनंत गुण हैं, जो इसे पीता है वह सुखी होता है, शक्तिशाली होता है और राजसी आनंद पाता है।" उनके यह शब्द सुनते ही आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कौन संत है जो शराब के गुण गा रहा है।

थोड़ी ही देर में यह समाचार स्वयं राजा तक पहुँचा। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन महात्मा है जो मदिरा की प्रशंसा कर रहा है। उसने तुरंत दूत भेजा और कहा कि उस महात्मा को ससम्मान दरबार में लाया जाए। महात्मा जी दरबार में आए, राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और कहा, "महाराज, मैंने सुना है कि आप मदिरापान के रहस्य जानते हैं। कृपा कर मुझे भी वह विधि बताइए जिससे मैं इसे बिना हानि के ग्रहण कर सकूं।"

महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, "राजन, मदिरा में गुण तो हैं, किंतु उसे शुद्ध किए बिना पीने से वह विष के समान हो जाती है। जैसे बिना संस्कार के औषधि भी मृत्यु का कारण बन सकती है, वैसे ही अशुद्ध मदिरा शरीर और मन दोनों को नष्ट करती है। यदि इसे शुद्ध कर लिया जाए, तो इसके दोष समाप्त हो जाते हैं।"

राजा बड़ी उत्सुकता से बोला, "महाराज, कृपा करके यह शुद्धि की विधि बताइए।"

महात्मा बोले, "राजन, इसके लिए एक सिद्ध मंत्र है। उस मंत्र का चौबीस लाख बार जप करने से जो माला सिद्ध हो जाती है, उसके प्रत्येक दाने में दिव्य शक्ति आ जाती है। जब उस माला का एक दाना मदिरा के प्याले में डाल दिया जाए और दाना बीच में डूबा रहे, तो मदिरा के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन एक नया दाना डालते जाना चाहिए, और जब एक सौ आठ दाने पूर्ण हो जाएँ, तब शुद्ध मदिरा तैयार होती है।"

राजा ने माथा पकड़ लिया, "महाराज, यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया है! मैं एक दिन भी मदिरा के बिना नहीं रह सकता, चौबीस लाख मंत्र-जप तो महीनों में पूरा होगा।"

महात्मा जी ने अपने गले से स्फटिक की माला उतारकर कहा, "जब तक तुम्हारी माला सिद्ध न हो जाए, तब तक यह मेरी माला रखो। यह सिद्ध है, इससे काम चलाओ।"

राजा ने आदरपूर्वक माला ली। उस रात उसने जैसे ही प्याले में माला का दाना डाला और मदिरा उंडेली, उसका रंग कुछ बदला हुआ लगा। राजा ने पी तो लिया, पर उसे उस रात नींद बहुत गहरी आई। अगली सुबह जब उठा, तो उसके भीतर एक अजीब-सा सुकून था। उसने स्नान करके महात्मा के बताए अनुसार मंत्र-जप आरंभ किया। धीरे-धीरे राजा को उस जप में आनंद आने लगा। अब वह दिन में कई घंटे जप करता और हर दिन एक दाना प्याले में डालता।

ज्यों-ज्यों उसकी माला आगे बढ़ी, त्यों-त्यों उसके भीतर का परिवर्तन होता गया। जहाँ पहले उसे मदिरा के बिना बेचैनी होती थी, अब वह जप के बिना असहज महसूस करता था। जब माला के लगभग सत्तर दाने पूरे हुए, तो उसके मन में स्वतः विचार आया—"मंत्र-जप और ईश्वर-स्मरण में जो आनंद है, वह मदिरा में कहाँ? यहाँ तो आत्मा झूम उठती है, वहाँ केवल शरीर नाचता है।"

उसी क्षण उसने प्याला ज़मीन पर दे मारा, आँखें बंद कीं और आँसुओं में डूबकर कहा—"महाराज, आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है।"

उसने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में मदिरा के सारे भंडार नष्ट कर दिए जाएँ। सभी विद्वानों और पुरोहितों को जेल से मुक्त कर सम्मानपूर्वक बुलाया गया। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा माँगी। कुछ ही दिनों में राज्य में धर्म, शांति और समृद्धि का युग लौट आया।

महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, "राजन, मदिरा को नहीं छोड़ा गया, उसे रूपांतरित किया गया। अब तुम्हारा मन बाहरी नशे में नहीं, भीतर के नशे में रम गया है—ईश्वरानंद में।"

इस प्रकार एक सिद्ध महात्मा की माला और मंत्र ने न केवल एक राजा को उसके दुर्व्यसन से मुक्त किया, बल्कि पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। यह कथा यही सिखाती है कि जब किसी व्यक्ति का मन ईश्वर की दिशा में मुड़ जाता है, तो संसार का कोई भी बंधन, कोई भी बुरी लत उसे रोक नहीं सकती। मंत्र की शक्ति, श्रद्धा की गहराई और आत्मजागरण का नशा सबसे महान है—जो एक बार चढ़ जाए, फिर किसी अन्य नशे की आवश्यकता नहीं रहती।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

गुजरात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी महिला ने कही पीड़ाभरी आपबीती, दो किलो अनाज और बेरोज़गारी पर उठाया सवाल

(जीएनएस)। अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे के दौरान जूनागढ़ के सासन स्थित सिंह सदन में आदिवासी समाज की महिलाओं से हुई बातचीत ने वहां उपस्थित अधिकारियों और कार्यक्रम आयोजकों को हैरान कर दिया। 10 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिलाओं से सीधे संवाद कर रही थीं। इसी दौरान एक महिला अचानक मंच पर आई और अपनी जीवन की कठिन परिस्थितियों और समस्याओं को साझा किया। महिला ने बताया कि उनके समुदाय को मात्र दो किलो राशन मिलता है और रोजगार के अवसर नगण्य हैं। उन्होंने कहा कि जब वे अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें दबा दिया जाता है। महिला ने राष्ट्रपति से कहा कि समाज में आर्थिक तंगी के कारण उनके लोग गरीबी की चपेट में हैं और उनके लिए शिक्षा, नौकरी और विकास के अवसर बहुत कम हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने महिला की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सीधे संवाद करते हुए स्थिति की गंभीरता को समझा।

महिला ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, "हमारे पास दो किलो राशन मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। हमारे लोगों में केवल दो-तीन को रोजगार मिलता है, बाकी पूरी तरह बेरोज़गार हैं। हमें आगे बढ़ने और अपने अधिकारों की मांग करने का अवसर नहीं दिया जाता। जब हम आवाज़ उठाते हैं, तो हमारी बात दबा दी जाती है।" राष्ट्रपति ने यह सुनकर महिला से पूछा कि क्या वास्तव में यह सब सच है, और उपस्थित अन्य लोगों ने भी पुष्टि की। इस संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें महिला की स्पष्ट बातें और राष्ट्रपति की संवेदनशील प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह घटना दर्शाती है कि सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति और उनके लाभार्थियों के बीच अंतर कितना बड़ा है। जमीनी स्तर पर आदिवासी समाज के लोग राशन, नौकरी और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे में सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश का दौरा भी किया। उन्होंने गिर सोमनाथ जिले में लायन सफारी का अनुभव किया और आदिवासी समूहों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सीधे सुना। इसके अलावा 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया और कहा कि राज्य में स्व-रोज़गार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस संस्कृति के संवाहक बनें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। यह घटना स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति जैसे संवेदनशील और सक्रिय नेता भी जब सीधे समाज की वास्तविक पीड़ा सुनते हैं, तो अधिकारियों और प्रशासन की निष्क्रियता और चुप्पी सामने आती है। आदिवासी समाज के लिए यह संदेश है कि उनके मुद्दे अनदेखे नहीं हैं, और उनकी आवाज़ अब उच्च स्तर पर भी पहुंचाई जा रही है। वहीं सरकार और प्रशासन के लिए यह चेतावनी है कि गरीब और वंचित समुदायों की समस्याओं को नजरअंदाज करना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है।

गुजरात में कपास किसानों के लिए आप का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी हिरासत में, पुलिस और सरकार पर तीखा आरोप

(जीएनएस)। अहमदाबाद/बोटाद। गुजरात में कपास किसानों के उचित मूल्य और उनके अधिकारों की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा बुलाई गई महापंचायत रविवार को नहीं हो सकी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को पुलिस ने बोटाद पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसुदान गढ़वी आप किसान सेल के नेता राजू करपड़ा के खिलाफ कार्रवाई और किसानों के हितों की रक्षा को लेकर बोटाद में महापंचायत बुलाई थी।

इसुदान गढ़वी ने हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2027 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पूरी गुजरात पुलिस बदल दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बोटाद के मार्केटिंग यार्ड में किसानों को उनकी कपास का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और व्यापारी गीली कपास के नाम पर भाव कम कर देते हैं।

महापंचायत में शामिल होने के लिए तैयार कई पार्टी नेता मौके पर नहीं पहुंच पाए। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रेश्मा पटेल और यूथ विंग के प्रमुख ब्रिजराज सोलंकी को भी पुलिस ने रोक लिया। इसुदान गढ़वी के साथ समत गढ़वी, सागर रबारी, गौरी देसाई, एचडी पटेल और किरण देसाई को पुलिस ने रोककर वाहनों में बिठाया और कई घंटे बाद छोड़ा। इसुदान गढ़वी ने सवाल उठाया कि क्या वे आतंकवादी हैं, जिन्हें रोकने के लिए सरकार इतनी सतर्क है। उन्होंने दावा किया कि बोटाड में आज महापंचायत न हो पाने के बावजूद निकट भविष्य में 50,000 से अधिक किसानों की मौजूदगी में बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 54 लाख किसानों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं और अगर सभी किसान सड़कों पर उतर आएं तो भाजपा सरकार को कौन बचाएगा।

इसुदान गढ़वी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी गुजरात बुलाकर किसानों की आवाज को मजबूत करेगी। उनका संदेश स्पष्ट था कि AAP किसानों को उनका हक दिलाने तक पीछे नहीं हटेगी और राज्य में किसानों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।

अलीगढ़ में करवाचौथ की रात 12 दुल्हनों ने जेवर और नकदी लेकर दिया बड़ा धोखा, बिहार से जुड़ा गिरोह सक्रिय

(जीएनएस)। अलीगढ़। करवाचौथ की रात अलीगढ़ में 12 दुल्हनों ने शादी के कुछ ही घंटे बाद अपने ससुराल वालों को बड़ा झटका दिया। सभी दुल्हनें जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी महिलाएं बिहार की रहने वाली थीं और शादी कराने वाले बिचौलियों के जरिए यहां आई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार बिचौलियों और उनके परिवार की तलाश में छापेमारी जारी है।

जानकारी के मुताबिक, सासनी गेट निवासी निहाल शर्मा और उनके बेटे प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी पहचान इगलास के सचिन ठाकुर से हुई, जिसने बिहार से आई युवतियों से शादी कराने का प्रस्ताव दिया। कुल 12 युवकों ने 12 युवतियों से शादी की। प्रतीक ने बताया कि उसने बिहार की शोभा से शादी के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि कैलाश नगर निवासी वीर सिंह प्रेमवीर ने मनीषा के लिए 1.30 लाख रुपये बिचौलियों को दिए। सभी शादियां शुक्रवार को सचिन ठाकुर के घर विधि-विधान से संपन्न हुईं, जहां फेरे और पूजा हुई।

शादी के बाद करवाचौथ का व्रत रखने और चांद देखने के बाद दुल्हनों ने भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर घरवालों को बेहोश कर दिया और जेवर व नकदी लेकर फरार हो गईं। सुबह घरवालों की नींद खुली तो घर के दरवाजे खुले और अलमारियां खाली मिलीं।

घटना की सूचना मिलने के बाद कुछ पीड़ित परिवारों ने बदनामी के डर से चुप्पी साधी, लेकिन शनिवार को चार पीड़ित पूर्व मेयर शकुंतला भारती के घर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद सासनी गेट थाने में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी हरि भान सिंह ने बताया कि शोभा, सचिन, मुकेश गुप्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ BNS की धारा 316(2), 305, 318(4), 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार यह कोई सामान्य ठगी नहीं बल्कि संगठित गिरोह की योजना थी, जो पहले भी कई जिलों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब पुलिस बिहार और इगलास में छापेमारी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना ने शादी और भरोसे के महकमे को हिला दिया है और लोगों में भय और चिंता भी बढ़ा दी है।

सरदार पटेल जयंती पर प्रदेशभर में "रन ऑफ यूनिटी" का भव्य आयोजन, योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यक्रमों का ऐलान

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में "रन ऑफ यूनिटी" सहित अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य युवाओं और आम जनता में सरदार पटेल के एकता और देशभक्ति के संदेश को पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान की शुरुआत पहले ही छह अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने डिजिटल माध्यम से की थी। इस डिजिटल फेज में युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और यंग लीडर्स प्रोग्राम में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल प्रतियोगिताएं नहीं हैं, बल्कि सरदार पटेल के विचारों और उनके आदर्शों को हर दिल तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के दूसरे चरण की भी घोषणा की। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश के गांव-गांव और गली-गली पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान योग और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, व्याख्यान और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं होंगी और नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया जाएगा। साथ ही, मोदी सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी और स्वच्छता अभियान भी इन गतिविधियों के हिस्से होंगे।

योगी ने बताया कि इन पदयात्राओं में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक, स्कूल और कॉलेज के छात्र, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, सेना के पूर्व जवान, बड़े खिलाड़ी और समाजसेवी भाग लेंगे। प्रत्येक संस्था अपने नाम के बैनर के साथ इन 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राओं में शामिल होगी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से चयनित 2 से 5 पदयात्री करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के नक्शे को जोड़कर रियासतों को एकजुट किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब हमारा लक्ष्य केवल भौगोलिक एकता ही नहीं, बल्कि दिलों और आत्माओं में भारत को एक करना है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और सरदार पटेल के अदम्य साहस, एकता और समर्पण के संदेश को युवाओं तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक एकता की भावना को मजबूत किया जाएगा।

गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन: योगी आदित्यनाथ ने नदी को जीवनधारा और सांस्कृतिक प्रतीक बताया

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 'गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन' की घोषणा करते हुए इसे केवल जल शुद्धिकरण का अभियान नहीं बल्कि उत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा के संरक्षण का व्यापक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि गोमती नदी पीलीभीत से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का जीवनधारा है और इसके संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर सतत प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने गोमती टास्क फोर्स की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी में कोई भी सीवरेज सीधे नहीं गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाई जाएं। उन्होंने अवैध बस्तियों और नदी तट पर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाने का भी निर्देश दिया, ताकि स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मिशन का दायरा पूरे नदी प्रवाह क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे गोमती पूरी तरह स्वच्छ, अविरल और निर्मल बने।

मुख्यमंत्री ने मिशन के प्रमुख लक्ष्यों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। नगरीय सीवेज का 95 प्रतिशत अवरोधन, नदी प्रदूषण को न्यूनतम करना, तटीय पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार, घाटों का सौंदर्यीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध इसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। लखनऊ में इकाना वेटलैंड और साजन झील जैसे नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोमती का पुनर्जीवन केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नदी के जैविक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनेगा।

बैठक में जनजागरूकता और तकनीकी सुधार पर जोर दिया गया। टास्क फोर्स ने नदी तटों पर पैदल और नौका गश्त, 1,000 टन से अधिक जलकुंभी की सफाई और नालों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है। 100 से अधिक जागरूकता अभियानों के जरिए 70,000 नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती का जल जीवन का आधार है और इसे स्वच्छ व अविरल बनाए रखना उत्तर प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मासिक बैठकों और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को अनिवार्य कर पारदर्शिता और जनसहभागिता पर विशेष बल दिया।

बैठक में मेजर जनरल सलिल सेठ, ब्रिगेडियर नवतेज सिंह सोहल, प्रो. (डॉ.) वेंकटेश दत्ता समेत कई विशेषज्ञ मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जब शासन और समाज मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी गोमती अपनी निर्मलता और जीवनदायिनी धारा पुनः प्राप्त कर सकेगी।"

प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र महुड़ी जाना हुआ और भी आसान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पिलवाई-महुड़ी फोरलेन रोड का किया लोकार्पण

▸▸ 20 करोड़ रुपए के खर्च से साढ़े चार किमी लंबी सड़क को सीमेंट-कंक्रीट फोरलेन में तब्दील किया

▸▸ दिवाली-काली चौदस के त्योहारों में महुड़ी दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन सुगम होगा

▸▸ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के सड़क नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने के लिए सीमेंट-कंक्रीट रोड निर्माण का सड़क एवं भवन विभाग का दृष्टिकोण

(जीएनएस)। गांधीनगर, 12 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र महुड़ी को पिलवाई से जोड़ने वाली 4.45 किलोमीटर लंबी फोरलेन सीमेंट-कंक्रीट सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क के निर्माण में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है।

इस रोड के फोरलेन बनने से महुड़ी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेगी, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी होगी।

इतना ही नहीं, अहमदाबाद-गांधीनगर से विजापुर को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सड़क एवं भवन विभाग को राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन के तहत विभाग ने सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों के निर्माण के जरिए मानसून में बरसाती पानी के चलते सड़कों को होने वाले नुकसान को रोकने का दृष्टिकोण अपनाया है।

तदनुसार, इस महुड़ी-पिलवाई रोड को भी सीमेंट-कंक्रीट से मजबूत और गुणवत्तायुक्त बनाया गया है।

सड़क को फोरलेन में तब्दील करने का यह काम 10 महीने में पूरा हुआ है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा दिवाली के त्योहारों से पहले इसका लोकार्पण करने से आगामी काली चौदस के अवसर पर विशाल संख्या में महुड़ी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन सुगम होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, समर्पण और सुशासन के 24 वर्ष पूरे होने और 25वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 7 से 15 अक्टूबर के दौरान राज्यव्यापी विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। इस विकास सप्ताह में पूरे राज्य में अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस विकास सप्ताह के अंतर्गत महुड़ी-पिलवाई सड़क के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माणसा के विधायक श्री जे.एस. पटेल सहित कई पदाधिकारी, अग्रणी और गांव के नागरिक उपस्थित रहे।

विकास सप्ताह : 13 अक्टूबर, शहरी विकास दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी गरीबों को दिए पक्के मकान, हर चेहरे पर खिल उठी मुस्कान

▸▸ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 9.09 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूर्ण

▸▸ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन के लिए गुजरात को अब तक कुल 14 अवॉर्ड मिले

(जीएनएस)। गांधीनगर : 7 अक्टूबर, 2025 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। विकास के इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए हर साल 7 से 15 अक्टूबर के दौरान विकास सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 12 और 13 अक्टूबर शहरी विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2005 में शहरी विकास वर्ष मनाकर योजनाबद्ध शहरी विकास की आधारशिला रखी थी।

आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात शहरीकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय शहरी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और निचले मध्यम वर्ग के परिवारों को उनके सपनों का घर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी अहम योजना क्रियान्वित की है और आज, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात इस योजना के कार्यान्वयन में देश का अग्रणी राज्य है।

शहरी गरीबों को मिला उनके सपनों का घर, 9.09 लाख से अधिक घरों का हुआ निर्माण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृढ़ विश्वास है कि शहरी विकास केवल अवसंरचना विकास ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक मार्ग भी है। इस ध्येय को सार्थक करते हुए उन्होंने 2015 में शहरी क्षेत्र के गरीबों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री की इस योजना से करोड़ों लोगों को उनके सपनों का घर मिला और उनके चेहरों पर मुस्कान खिली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य में 9.09 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो एक उल्लेखनीय सफलता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में गुजरात अग्रणी

गुजरात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। पीएमएवाई (शहरी) के क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके पहले आवास पर लिए गए होम लोन पर ब्याज सहायता का लाभ प्रदान करने में गुजरात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी स्थान पर है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (एआरएचसी) के तहत शहरी गरीबों और कामगारों को किफायती किराए का घर प्रदान करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तीन महीने के भीतर ही गुजरात, सूरत शहर के सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 के अंतर्गत किराए के मकानों में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी-इंडिया के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चयनित छह राज्यों में से गुजरात का राजकोट शहर एक था। राजकोट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ईडब्ल्यूएस-2 श्रेणी के कुल 39.77 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया वाले कुल 1144 आवासों का निर्माण किया गया है।

पीएमएवाई (शहरी) के लिए गुजरात को अब तक मिले कुल 14 अवॉर्ड

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में गुजरात को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के अंतर्गत प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को पीएम आवास योजना के लिए 3 अवॉर्ड प्रदान किए गए। साथ ही, लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत गुजरात राज्य के 3 लाभार्थियों को बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में अवॉर्ड दिए गए। बाद में, 2022 में केंद्र सरकार ने गुजरात को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में अवॉर्ड प्रदान किए। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गुजरात को अब तक कुल 14 अवॉर्ड प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता के बाद सितंबर-2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की घोषणा की गई थी। यह देश भर में आगामी 5 वर्षों में (2024-2029) 1 करोड़ पक्के मकान बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत लोग अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी), लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस), अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (एआरएच) घटकों के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 29,821 आवास मंजूर किए गए हैं।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (सैक),
निर्माण एवं अनुरक्षण समूह (सीएमजी), विद्युत एवं फायर अलार्म प्रणाली विभाग, जोधपुर टेकरा अंबावाडी विस्तार पो.ऑ., अहमदाबाद – 380015
दूरभाष सं : (079) 26914911/05/20, फैक्स सं. (079) 26915800

ई-निविदा सूचना सं: (i) सैक/सीएमजी/ईएफएएसडी/एम/20/2025-26 दिनांक: 07.10.2025

ई-निविदा आमंत्रण हेतु संक्षिप्त सूचना

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा माध्यम से ओनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा में दी गई अनुमानित लागत	कार्य पूरा होने की अवधि	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अवधि	निविदा पाने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की अंतिम तिथि एवं समय	बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.) (₹)
1.	एम20 - 39 एकड़ के नए एसएसी परिसर, बोपल, अहमदाबाद में जीएलआर और नर्मदा जल पा□पला□न नेटवर्क के लिए स्टार्टर पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग - विद्युत कार्य।	₹ 21.30 लाख	04 माह	13.10.2025 को 10:00 बजेसे 26.10.2025 को 17:00 बजे तक	30.10.2025 को 17:00 बजे तक	31.10.2025 को 11:00 बजे (तकनीकी एव वाणिज्यिक बोली)	₹ 42,600/-

2. निविदा दस्तावेज निविदाविजार्ड के साथ पंजीयन तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करते हुए ई-निविदा वेबसाईट www.tenderwizard.com/ISRO से निर्धारित अवधि के दौरान डाऊनलोड किए जा सकते है | विक्रेता के पंजीयन करने की प्रक्रिया □स वेबसाईट में प्रदर्शित की गई है | निविदा प्रक्रिया शुल्क मेसर्स. आईटीआई लि. को ई-गेटवे के माध्यम से भुगतान करे |

3. अर्हता मापदंड एवं अन्य ब्यौरे के लिए □च्छुक निविदाकार निविदा आमंत्रण हेतु विस्तृत सूचना (एन.आई.टी.) वेबसा□ट www.isro.gov.in या www.sac.gov.in साथ ही www.tenderwizard.com/ISRO के टेन्डर फ्री व्यू में देख सकते है।

समूह प्रधान, सीएमजी/सैक

मेडागास्कर में जनविरोध उफान पर — राजधानी में गोलीबारी, तीन घायल, सैनिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

(जीएनएस)। अफ्रीकी द्वीप देश मेडागास्कर में पिछले एक महीने से चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। राजधानी एंटानानारिवो में राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। यह झड़प CAPSAT बैरक (Comando de la Police et des Services Administratifs et Techniques) के पास हुई, जहां कुछ सैनिकों ने भी सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि देश में "सत्ता पर अवैध और जबरन कब्जा करने की कोशिश" की जा रही है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी सैन्य या असैन्य संगठन यदि लोकतांत्रिक ढांचे को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह आंदोलन 25 सितंबर 2025 से शुरू हुआ था, जब हजारों लोग राजधानी में पानी, बिजली और ईंधन की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन राष्ट्रपति राजोइलिना के शासन के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक विद्रोह का रूप ले चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन का नेतृत्व अब वही CAPSAT यूनिट कर रही है, जिसने 2009 में राजोइलिना को सत्ता में आने में मदद की थी।

रविवार को हुई झड़प के दौरान प्रदर्शनकारी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने "देश के सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है।" उनका कहना है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असफल रही है।

प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा और छात्र शामिल हैं, जिन्हें "जेन-जी आंदोलन" कहा जा रहा है। वे नेपाल और केन्या में हुए हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों से प्रेरित बताए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। शनिवार को हुई एक हिंसक झड़प में CAPSAT के एक सैनिक की मौत ने आंदोलन को और भड़का दिया। रविवार को हजारों लोग उसकी याद में शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हुए। इस जुलूस में चर्च के नेता, विपक्षी राजनेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्क रावलोमाना भी मौजूद थे। रावलोमाना ने कहा, "यह लड़ाई सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और संविधान की बहाली के लिए है।" पुलिस और जेंडरमेरी पर बल प्रयोग के आरोप लगे हैं। हालांकि जेंडरमेरी का कहना है कि उन्हें केवल राष्ट्रीय कमांड सेंटर से आदेश मिलते हैं और वे "स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश" कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेडागास्कर की स्थिति बेहद नाजुक है। अगर CAPSAT यूनिट के भीतर विद्रोह फैलता है, तो देश एक बार फिर सैन्य संकट की ओर बढ़ सकता है, जैसा कि 2009 में हुआ था।

राजधानी एंटानानारिवो में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बाधित कर दी गई हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। नागरिक संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह मेडागास्कर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल मेडागास्कर की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि अफ्रीका के कई देशों में लोकतांत्रिक ढांचा किस तरह सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और सत्ता के केंद्रीकरण के बीच डगमगा रहा है।

काली चौदस से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, महुडी-पिलवई फोरलेन सड़क का उद्घाटन

(जीएनएस)। गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को महुडी जैन तीर्थ स्थल को पिलवई से जोड़ने वाली 4.45 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने इस सड़क का निर्माण 20 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन में कराया है। इस परियोजना के पूरा होने से महुडी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी, यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। साथ ही अहमदाबाद-गांधीनगर से विजापुर तक के मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर सड़क एवं भवन विभाग ने इस मार्ग को मजबूत और टिकाऊ बनाने के साथ मानसून में बारिश के पानी से होने वाली क्षति से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट-कंक्रीट का उपयोग किया। महुडी-पिलवई सड़क का यह चार लेन का निर्माण कार्य मात्र 10 महीनों में पूरा हुआ। दिवाली और काली चौदस से पहले इसे उद्घाटन करने से तीर्थयात्रियों के लिए महुडी मंदिर तक आने-जाने की सुविधा और सहज होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, समर्पण और सुशासन के 24 वर्ष पूरे होने और 25वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 7 से 15 अक्टूबर तक गुजरात में राज्यव्यापी विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी विकास सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री ने महुडी-पिलवई फोरलेन सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनासा विधायक जे.एस. पटेल, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। इस नई सड़क के उद्घाटन से महुडी तीर्थ स्थल के दर्शन करने आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को न केवल बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए समय और संसाधनों की भी बचत होगी। राज्य सरकार की यह पहल स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी और आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास में भी योगदान देगी।

SGPC ने चिदंबरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार बयान को खारिज किया: 'यह साझा फैसला नहीं, इंदिरा गांधी का निजी एजेंडा था'

(जीएनएस)। नई दिल्ली/अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर हालिया बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। SGPC ने कहा कि चिदंबरम ने अपने बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार को 'साझा फैसला' बताकर तथ्यात्मक रूप से तोड़ा-मरोड़ा है। कमेटी ने स्पष्ट किया कि जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पर चलाया गया सैन्य अभियान पूरी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निजी और एकतरफा निर्णय था, न कि सेना, पुलिस या खुफिया विभाग का साझा निर्णय।

SGPC ने चिदंबरम के बयान को "आधा सच" करार देते हुए इसे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कमेटी ने कांग्रेस से अपील की कि वह इस मामले में पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे और सच्चाई सार्वजनिक रूप से सामने लाए। SGPC ने कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, तो राहुल गांधी 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी नेताओं जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर खुलकर क्यों नहीं बोलते।

चिदंबरम ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत निर्णय था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं, बल्कि सेना और अन्य विभागों का साझा निर्णय था। SGPC ने इसे पूरी तरह असत्य बताते हुए कहा कि यह कदम केवल इंदिरा गांधी के निजी एजेंडे का परिणाम था।

चिदंबरम के बयान ने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हलचल मचा दी है। वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि "50 साल बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कांग्रेस और इंदिरा गांधी को दोष देने की क्या जरूरत थी। यह वही रवैया है, जो बीजेपी और प्रधानमंत्री अपनाते हैं।" अल्वी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या चिदंबरम किसी दबाव में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी आपराधिक मामले लंबित हैं। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाने के लिए सेना ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में भिंडरावाले और कई समर्थक मारे गए और स्वर्ण मंदिर को गंभीर क्षति हुई। सिख समुदाय ने इसे अपने पवित्र स्थल का अपमान माना। इसके कुछ महीनों बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी, जिसके बाद दिल्ली और अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों सिखों की जान गई।

SGPC का कहना है कि इतिहास को सही ढंग से पेश करना जरूरी है और किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना सिख समुदाय के प्रति अन्याय है। कमेटी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह पूरे मामले की सच्चाई को स्वीकार करे और सिखों के दुख और आक्रोश का सम्मान करे।

असम की जनसंख्या में बड़ा बदलाव, CM हिमंत बिस्वा सरमा का दावा: हिंदू आबादी घटकर 40%, मुस्लिम आबादी करीब 39.5%

(जीएनएस)। गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम में हिंदुओं की आबादी अब कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत रह गई है, जो मुस्लिम आबादी के लगभग बराबर है। मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को "जनसांख्यिकीय परिवर्तन का बड़ा असर" बताते हुए आगाह किया कि यदि अन्य समुदायों को अलग रखा जाए, तो असम में हिंदू आबादी अब 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2021 के अनुमानों के अनुसार, मुस्लिम आबादी अब राज्य की कुल आबादी का लगभग 39.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि ईसाई आबादी 6-7 प्रतिशत के बीच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े 2011 की जनगणना और उसके बाद के अनुमानों पर आधारित हैं। मुख्यमंत्री ने इस जनसांख्यिकीय बदलाव की मुख्य वजह अवैध घुसपैठ को बताया। उन्होंने कहा कि वैष्णव संस्कृति का केंद्र और दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप माजुली जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वृद्धि स्थानीय मुसलमानों की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के कारण हुई।

सरमा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 'जनसांख्यिकी मिशन' का समर्थन करते हुए इसे इस मुद्दे के समाधान की दिशा में पहला निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा एक सकारात्मक पहल है, जो असम और अन्य प्रभावित राज्यों में संतुलित जनसंख्या सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

2011 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदुओं की आबादी लगभग 61.47 प्रतिशत थी, जबकि मुस्लिम आबादी 34.22 प्रतिशत थी। मुख्यमंत्री के हालिया दावे इस समय सामने आए हैं जब असम में अवैध घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। इस बयान ने राज्य में जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचना पर नई बहस को जन्म दिया है।

धीरेंद्र शास्त्री का दिवाली पर विवादित बयानः 'पटाखों पर दूसरों से ज्ञान न लें'

(जीएनएस)। मुंबई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिवाली को लेकर चल रही बहस में अपनी राय व्यक्त करते हुए एक विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान शास्त्री ने कहा, "हम तो पटाखे फोड़ेंगे, कृपया इस पर हमें उपदेश न दें। हम न तो आपके बकरीद पर ज्ञान देते हैं, न ही ताजिया पर, तो आप भी होली और दिवाली पर ज्ञान न दें।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और दिवाली के दौरान सीमित पटाखा चलाने के आदेश जारी किए हैं। शास्त्री ने कहा कि वह जानते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन उनका मानना है कि यह केवल दिवाली तक ही सीमित है और इसे लेकर दूसरों से उपदेश लेना उचित नहीं है।

धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली हैं; कुछ ने उनका समर्थन किया है, तो कुछ ने आलोचना की है। उनके इस बयान ने पटाखों पर चल रही बहस को और तेज कर दिया है और ऑनलाइन मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई है।

मुंबई दौरे पर शास्त्री ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन किए और श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ महाराष्ट्र में प्रवचन दिए। भिवंडी में आयोजित तीन दिनों की श्रीमद्भागवत कथा में उन्होंने विशेष प्रवचन देकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। उनके बयान ने दिवाली और त्योहारों के दौरान सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी नई बहस को जन्म दिया है।

पुणे में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लीलता का मामला: 46 वर्षीय शिक्षक गिरफ्तार

(जीएनएस)। पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में 46 वर्षीय सुरेश दौलत रौंदल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्वारगेट के गौरव राज बिल्डिंग, दत्तनगर, अंबेगांव, कात्रज का निवासी है और इलाके में एक निजी ट्यूशन क्लास संचालित करता है।

घटना गुरुवार, 9 अक्टूबर सुबह लगभग 7:45 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक, उस समय छात्रा क्लास में अकेली थी। आरोपी रौंदल ने कथित तौर पर छात्रा से अश्लील बातें की और उसे प्रभावित करने के लिए कहा कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे अपने स्कूल में नौकरी दिलाएगा और एक सोने की अंगूठी भी देगा।

छात्रा इस घटना से डर गई और तुरंत अपने परिवार को सूचित किया। परिजनों ने स्वारगेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

रौंदल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। मामले की जांच में आरोपी के पिछले रिकॉर्ड और उसके क्लास में आने वाले अन्य छात्रों के अनुभवों को भी शामिल किया जा रहा है।

पुलिस ने चेताया है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कड़ा कानून है और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय समाज और अभिभावक भी सतर्क रहने और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

पालघर हत्या मामले की फरार महिला मुंबई से गिरफ्तार

(जीएनएस)। पालघर। 2020 में हुए एक हत्या के मामले में आरोपी महिला डोलरिन अफरीन अहमद खान (27) को पांच साल से अधिक समय फरार रहने के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी विशेष सूचना के आधार पर की गई।

घटना 12 फरवरी, 2020 की है, जब नालासोपारा की रहने वाली डोलरिन अफरीन ने पालघर के अर्नाला में प्रदीप दयाशंकर राय (23) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी और पड़ोसी (ठाणे जिले के बदलापुर निवासी) के बीच पैसे के विवाद के कारण यह हत्या हुई। महिला ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की थी।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी के लंबे समय तक फरार रहने के कारण पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया, जिससे फरार आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति मिली।

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने बताया कि पिछले चार महीनों में टीम ने आरोपी का पता लगाने के प्रयास तेज़ कर दिए थे। एक विशेष सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने उसे मुंबई के कांदिवली इलाके में पाया और 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए अर्नाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और इस मामले की गिरफ्तारी से न्याय की प्रक्रिया को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों और परिवारों को भी अपराध के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान से पाकिस्तान में मचा बवाल, कश्मीर को लेकर भड़का इस्लामाबाद

(जीएनएस)। नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी साझा बयान ने दक्षिण एशिया की राजनीतिक फिज़ा में नया तनाव पैदा कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इन दिनों सात दिवसीय भारत दौरे पर हैं, और इसी दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति और सहयोग पर चर्चा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। यही बात पाकिस्तान को बुरी तरह नागवार गुज़री है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है और कश्मीर की कानूनी स्थिति को बदलने की कोशिश है। इस्लामाबाद ने दावा किया कि भारत और अफगानिस्तान का यह रुख "कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और उनके बलिदानों के प्रति असंवेदनशील" है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह क्षेत्रीय शांति के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए कश्मीर के मुद्दे को इस्तेमाल कर रहा है।

दूसरी ओर, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ संवाद पूर्णतः कूटनीतिक और सहयोगात्मक बताया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा की थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत और अफगानिस्तान ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत के साथ मुलाकात के दौरान साफ कहा, "हम मानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। हमने हमेशा कहा है कि विवाद और हिंसा से समस्याएं हल नहीं होतीं। बातचीत और आत्मनिरीक्षण ही सही रास्ता है। पाकिस्तान को अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए।" मुत्तकी के इस बयान ने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में और हलचल मचा दी है। इस्लामाबाद के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुत्तकी का यह बयान न केवल भारत के प्रति अफगानिस्तान के झुकाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि काबुल अब पाकिस्तान के दबाव में नहीं है। लंबे समय तक तालिबान सरकार को पाकिस्तान का समर्थक माना जाता रहा, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया कि काबुल अब स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा में बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिकों ने इसे "डिप्लोमैटिक सेटबैक" कहा है। उनके अनुसार, भारत ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को फिर से सशक्त करने का जो प्रयास किया है, वह पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई की अवधारणा पर सीधा प्रहार है। वहीं, भारतीय कूटनीतिज्ञों ने इसे क्षेत्र में "स्थिरता और विकास की दिशा में स्वाभाविक कदम" बताया है। अफगानिस्तान में भी मुत्तकी के बयान को सकारात्मक नजर से देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया में इसे "भारत के साथ नई दोस्ती की शुरुआत" कहा गया है। काबुल के राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता रहा है, और मौजूदा सरकार भी इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है।

पाकिस्तान के अंदर हालांकि इस बयान ने विरोधी दलों को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है, जिसके कारण अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी अब पाकिस्तान से दूरी बनाने लगे हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर यह विवाद एक नए शक्ति-संतुलन की ओर संकेत कर रहा है, जहां भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकियां पाकिस्तान की चिंताओं को और गहरा रही हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस तनाव के बावजूद तीनों देशों के बीच कोई संवाद की संभावना बची है या दक्षिण एशिया एक बार फिर भू-राजनीतिक टकराव के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

पप्पू यादव का दावा — "नीतीश कुमार को हटाने का अभियान पूरा, संजय झा ने निभाई मुख्य भूमिका"

(जीएनएस)। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने का षड्यंत्र एनडीए के अंदर ही रचा गया था और यह मिशन अब पूरा हो चुका है। उनके मुताबिक, इस पूरी साजिश को सफल बनाने में जेडीयू नेता संजय झा की प्रमुख भूमिका रही। पप्पू यादव ने अपने बयान में लिखा — "संजय झा ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिश सफल रही। अब बिहार को एक बार फिर दिल्ली के इशारों पर चलने वाली सरकार दी जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि "अति पिछड़ा और दलित समाज अब जागे, क्योंकि बीजेपी और उनके सहयोगी आपकी जमीन, रोजगार और सम्मान छीनने में लगे हैं।" इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू ने पप्पू यादव के आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि संजय झा पर आरोप लगाना केवल राजनीतिक स्टंट है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सबसे अनुभवी नेता हैं और उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी बीच एनडीए में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) को 101–101 सीटें दी गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (चिराग पासवान गुट) को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक जनता दल (उपेंद्र कुशवाहा) को 6 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (जीतनराम मांझी) को भी 6 सीटें मिली हैं। इस तरह कुल 243 विधानसभा सीटों का वितरण एनडीए के भीतर आपसी सहमति से तय कर लिया गया है।

चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा, "एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब बिहार तैयार है, और हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे।" जीतन राम मांझी ने भी संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें मिली सीटों से कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि वे एकजुट होकर एनडीए को सत्ता में वापस लाने का प्रयास करेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह सीट बंटवारा एनडीए के भीतर एकता और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने इसे "शानदार आगाज़ और विजय अभियान का श्रीगणेश" बताया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव का बयान उस समय आया है जब नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता और एनडीए में उनकी स्थिति को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी के भीतर कुछ नेता लगातार यह संकेत देते रहे हैं कि चुनाव के बाद नेतृत्व में बदलाव संभव है। ऐसे में पप्पू यादव का दावा इन अटकलों को और हवा देता दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से अभी कोई सीधा बयान नहीं आया है। लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वे पूरी तरह सक्रिय हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा मानकर मैदान में उतरेंगे। बिहार की सियासत में एक बार फिर आरोपों, गठबंधनों और रणनीतियों का खेल चरम पर है — और इसका परिणाम 2025 के चुनावी नतीजों से तय होगा कि सत्ता की बागडोर आखिर किसके हाथ में जाती है।